

RBI द्वारा जमा चुनौतियों पर हृदयत तथा HFC के लिये तरलता संबंधी नयिमों में सख्ती

प्रलिस के लिये:

[भारतीय रज़िर्व बैंक](#), [आवास वतित कंनयिों](#), [गैर-बैंकगि वतितिय कंनयिों](#), [मयूचुअल फंड](#), [नकद आरकषति अनुपात](#), [तरलता कवरेज अनुपात \(LCR\) ढाँचा](#)

मुख्य परीकषा के लिये:

धीमी जमा वृद्धिपर चतिाँ, बैंकगि कषेत्र की तरलता और जमा वृद्धि, गैर-बैंकगि वतितिय कंनयिों (NBFC)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में कयों?

हाल ही में [भारतीय रज़िर्व बैंक](#) (Reserve Bank of India- RBI) के गवरनर ने बैंकों से जमा वृद्धिको बढ़ावा देने के लिये नवीन उत्पाद वकिसति करने का आग्रह कयिा है।

- यह ऋण मांग में वृद्धिकी तुलना में जमा वृद्धिदर धीमी होने के कारण हुआ है, जसिसे बैंकगि कषेत्र की तरलता के लिये संभावति जोखमि उत्पन्न हो गया है।
- एक अन्य घटनाक्रम में, RBI ने [आवास वतित कंनयिों](#) (Housing Finance Companies- HFC) के लिये तरलता मानदंडों को कड़ा कर दयिा है, तथा उन्हें [गैर-बैंकगि वतितिय कंनयिों](#) (Non-Banking Financial Companies- NBFC) के नयिमों के अनुरूप कर दयिा है, ताकि इन संस्थाओं की वतितिय स्थरिता को मजबूत कयिा जा सके।

जमा वृद्धिके संबंध में चतिाँ कयिा हैं?

- ऋण बनाम जमा वृद्धि: ऋण-जमा अनुपात 20 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है, जसिमेंबैंक जमा में वर्ष-दर-वर्ष 11.1% की वृद्धि हुई है, जबकिऋण वृद्धि17.4% रही है।
 - बैंक जमा की वृद्धि, ऋण मांग में वृद्धिके साथ तालमेल नहीं रख पाई है, जसिसे ऋण और जमा वृद्धिके बीच अंतर बढ़ता जा रहा है।
- अल्पावधि जमा पर नरिभरता: बैंक ऋण मांग को पूरा करने के लिये अल्पावधिजमा और अन्य देयता साधनों का उपयोग तेज़ी से कर रहे हैं, जसिसे संरचनात्मक तरलता चुनौतियिों उत्पन्न हो सकती हैं।
- वैकल्पिक निवेश की ओर रुख: परिवार अपनी बचत को बैंक जमा से हटाकर [मयूचुअल फंड](#), [सूटॉक](#), [बीमा](#) और पेंशन फंड में लगा रहे हैं। यह बदलाव, शुद्ध वतितिय परसिपत्तियिों में गरिावट (2020-21 में GDP के 11.5% से 2022-23 में 5.1% तक) और बढ़ती [मुद्रास्फीति](#) के साथ, जमा वृद्धिको धीमा करने में योगदान देता है।
 - [भारतीय शेयर बाज़ारों](#) के मजबूत प्रदर्शन के कारण [निवेशक पारंपरिक बैंक जमाओं की तुलना में इक्विटी को अधिक पसंद कर रहे हैं](#)।
 - इस बदलाव ने जमा में धीमी वृद्धिमें योगदान दयिा है, जैसा कि मयूचुअल फंड उद्योग [कीप्रबंधन के तहत परसिपत्तियिों \(Assets Under Management- AUM\)](#) के अप्रैल 2019 में 24.79 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर अप्रैल 2024 में 57.26 लाख करोड़ रुपए हो जाने से स्पष्ट है।
- वनिधिमक आवश्यकताएँ: जुटाई गई जमाराशियिों का एक हसिसा [नकद आरकषति अनुपात \(CRR\)](#) और [वैधानिक तरलता अनुपात \(SLR\)](#) जैसी वनिधिमक आवश्यकताओं में बँधा हुआ है, जसिसे बैंकों के पास कम उधार देने योग्य नधियिों रह जाती हैं और जमाराशियिों के लिये प्रतसिपर्धा बढ़ जाती है।
 - जमाराशिऔर ऋण वृद्धिके बीच बढ़ता हुआ अंतर बैंकगि प्रणाली की स्थरिता को खतरे में डाल सकता है, यदइसे सक्रयि उपायों से हल नहीं कयिा जाता है।
- बढ़ी हुई प्रतसिपर्धा: बैंकों को न केवल एक-दूसरे से बल्कि उच्च-रटिरन इक्विटी-लकिड उत्पादों से भी प्रतसिपर्धा का सामना करना पड़ता है। मजबूत प्रदर्शन और बढ़ती वतितिय साक्षरता के कारण निवेशक तीव्रता से इक्विटी बाज़ारों की ओर रुख कर रहे हैं।
- तरलता जोखमि प्रबंधन पर प्रभाव: बैंकों ने [जमा प्रमाणपत्रों \(CD\)](#) पर अधिक विश्वास करके ऋण-जमा अंतर को कम करने का प्रयास कयिा है। हालांकि इससे ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के प्रतउनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है और तरलता जोखमि प्रबंधन जटलि हो जाता है, जसिसे प्रणाली

बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है।

- **वविकपूर्ण तरलता प्रबंधन की आवश्यकता:** सक्रिय तरलता प्रबंधन आवश्यक है। आरबीआई इन उभरती चुनौतियों से निपटने के लिये **तरलता कवरेज अनुपात (LCR)** ढाँचे की समीक्षा कर रहा है, साथ ही दृष्टिकोण को परिष्कृत करने के लिये सार्वजनिक परामर्श की योजना बना रहा है।

बैंक जमा वृद्धि को बढ़ाने के लिये कौन-सी रणनीति अपना सकते हैं?

- **मुख्य व्यवसाय पर ध्यान दें:** भारत के वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बैंकों को जमा जुटाने और उधार देने के अपने प्राथमिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गतिविधियाँ बैंक की "बरेड एंड बटर" हैं।
 - शाखा नेटवर्क का विस्तार, विशेष रूप से कम सेवा वाले या ग्रामीण क्षेत्रों में, बैंकों को नए ग्राहक खंडों तक पहुँचने में मदद कर सकता है, जिससे कुल जमा प्रवाह में वृद्धि हो सकती है।
- **नवीन जमा जुटाना:** बैंकों को आकर्षक और अभिनव उत्पादों को प्रस्तुत करके जमा जुटाने में आक्रामक होने के लिये प्रोत्साहित किया गया, जिससे ब्याज दरों का प्रबंधन करने हेतु RBI द्वारा दी गई स्वतंत्रता का लाभ उठाया जा सके।
 - वित्त मंत्री ने बैंकों से थोक जमा पर बहुत अधिक निर्भरता से बचने और इसके बजाय छोटे बचतकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, जो टिकाऊ बैंक संचालन के लिये महत्वपूर्ण हैं।
- **लचीले उत्पाद:** बैंक कर-बचत वाली सावधि जमाओं के लिये लॉक-इन अवधि को पाँच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करने पर विचार कर सकते हैं, जिससे वे म्यूचुअल फंड और इक्विटी-लिंक्ड बचत योजनाओं (ELSS) जैसे वैकल्पिक निवेश विकल्पों के साथ अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें।
- **प्रोत्साहन और प्रोन्नति:** ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु नई जमाओं के लिये आकर्षक ब्याज दरें, बोनस या नकद प्रोत्साहन प्रदान करना।
 - बचत खातों और सावधि जमा पर उच्च ब्याज दर की पेशकश से अधिक जमा आकर्षित हो सकते हैं, विशेषकर जोखिम से बचने वाले ग्राहकों से, जो इक्विटी से संभावित रूप से उच्च, लेकिन अनिश्चित रिटर्न की तुलना में स्थिर रिटर्न पसंद करते हैं।
- **प्रौद्योगिकी:** बैंक व्यक्तिगत बचत और जमा उत्पादों की पेशकश करने के लिये डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर सकते हैं, जिससे ग्राहकों के लिये अपनी बचत का प्रबंधन और वृद्धि करना आसान हो जाता है।
 - उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस और वित्तीय नयोजन उपकरणों के साथ मोबाइल बैंकिंग ऐप अधिक जमा को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- **ग्राहक जुड़ाव:** लक्षित विपणन अभियानों और लॉयल्टी प्रोग्राम के माध्यम से ग्राहक संबंधों को सुदृढ़ करना मौजूदा ग्राहकों को अपनी जमा राशि बढ़ाने एवं नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है।
 - वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना जो ग्राहकों को बचत के महत्त्व और बैंक जमा की सुरक्षा के बारे में शिक्षित करते हैं, जमा वृद्धि को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

HFC के लिये RBI के नए चलनधिमानदंड क्या हैं?

- **नई चलनधि आवश्यकताएँ:** सार्वजनिक जमा जुटाने वाली HFC को अब वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये अधिक चल परसिंपत्त बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
 - चल परसिंपत्त की आवश्यकता को चरणों में 13% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है: HFC को 1 जनवरी 2025 तक चल परसिंपत्त को 14% तक बढ़ाना होगा। जुलाई 2025 तक इस प्रतिशत को और बढ़ाकर 15% करना होगा।
 - HFC को अब सार्वजनिक जमा स्वीकार करना जारी रखने के लिये कम से कम एक वर्ष में न्यूनतम नविश-ग्रेड क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करना आवश्यक होगा।
 - यदि किसी HFC की क्रेडिट रेटिंग आवश्यक ग्रेड से नीचे आती है, तो उसे रेटिंग में सुधार होने तक मौजूदा जमा को नवीनीकृत करने या नए जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - यह उपाय सुनिश्चित करता है कि केवल वित्तीय रूप से सुदृढ़ HFC ही सार्वजनिक जमा स्वीकार कर सकते हैं, जिससे जमाकर्ताओं के लिये जोखिम कम हो जाता है।
 - HFC में सार्वजनिक जमा के लिये अधिकतम अवधि दस वर्ष से घटाकर पाँच वर्ष कर दी गई है।
 - पाँच वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली मौजूदा जमा राशियों को उनकी मूल शर्तों के अनुसार परिपक्व होने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन नई पाँच वर्ष की सीमा से अधिक नहीं हो सकती।
 - अवधि में यह कमी दीर्घकालिक चलनधि जोखिमों को कम करने में मदद करती है।
 - RBI ने HFC द्वारा रखी जाने वाली सार्वजनिक जमा राशि की अधिकतम सीमा को तीन गुना से घटाकर 1.5 गुना कर दिया है। इस नई सीमा से अधिक जमा राशि रखने वाली HFC को तब तक नई जमा राशि स्वीकार करने या मौजूदा जमा राशि को नवीनीकृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वे संशोधित सीमा का अनुपालन नहीं करती हैं।
 - इस उपाय का उद्देश्य आवास वित्त कंपनियों द्वारा अत्यधिक ऋण लेने से रोकना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपनी देनदारियों और परसिंपत्तियों के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखें।
- **NBFC वनियमों के साथ संरेखण:** पहले, HFC विशेष रूप से जमा स्वीकृति के संदर्भ में NBFC की तुलना में अधिक शक्तिशाली वविकपूर्ण मानदंडों के तहत कार्य करते थे।
 - RBI के नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य HFC को जमा स्वीकार करने वाली NBFC के समान मानते हुए इन वसिगतियों को दूर करना है। यह संरेखण सभी NBFC श्रेणियों में जमा स्वीकृति से जुड़ी एक समान वनियामक चर्चाओं को संबोधित करता है।

आवास वित्त कंपनियाँ

- HFC कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित विशेष संस्थाएँ हैं, जिन्हें शुरू में **नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB)** द्वारा वनियमित किया जाता था। हालाँकि, वर्ष 2019 में HFC पर वनियामक प्राधिकरण RBI को हस्तांतरित कर दिया गया था।
- इन कंपनियों को वभिन्न आय समूहों में आवास ऋण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये बनाया गया था। समय के साथ, HFC होम लोन का एक

प्रमुख स्रोत बन गए हैं और प्रायः अपने अधिक लचीले ऋण देने की पद्धतिके कारण ऋण वितरण मात्रा में पारंपरिक बैंकों से आगे निकल जाते हैं।

?????? ???? ?????:

प्रश्न. पारंपरिक बैंक जमा से वैकल्पिक निवेश की पद्धति में बदलाव का भारतीय वित्तीय प्रणाली पर प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये। बैंक जमा को बनाए रखने और आकर्षित करने के लिये क्या उपाय कर सकते हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

?????????:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर वचिार कीजिये: (2021)

1. केंद्र सरकार द्वारा रज़िर्व बैंक (आर.बी.आई.) के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है।
2. भारतीय संवधान के कतपिय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहति में आर.बी.आई. को नरिदेश देने का अधिकार देते हैं।
3. आर.बी.आई. का गवर्नर अपना अधिकार (पावर) आर.बी.आई. अधिनियम से प्राप्त करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rbi-highlights-deposit-challenges-and-tightens-hfc-liquidity-norms>

